बिहार में भाजपा की हार : काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती

विशेष प्रतिनिधि

बिहार में भाजपा की हार ने मोदी.अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है। इस हार के बाद भाजपा में मोदी विरोधी खेमा सक्रिय हो गया है और मोदी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिए गए भाजपा के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि इस हार के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। लेकिन आरएसएस अभी भी बिहार की हार से कोई सीख लेने को तैयार नहीं दिख रहा। अरुण जेटली ने हार के लिए सामूहिक जिम्मेदारी तय किए जाने की बात कही, पर इसे लेकर भाजपा में मतैक्य नहीं है। भूलना नहीं होगा कि बिहार में चुनाव मोदी बनाम नीतीश.लालू होकर रह गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच दौर में हुए विधानसभा चुनाव के लिए करीब 30 चुनावी रैलियां की थीं। खास बात यह रही कि जहां.जहां नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, वहां भाजपा को सबसे कम सीटें मिलीं। इस तरह, बिहार विधानसभा चुनाव ने यह दिखा दिया कि मोदी का जादू खत्म हो गया है। वे जनता का विश्वास खो चुके हैं। लोग उनके वायदों की असलियत समझ चुके हैं और यह सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से घटता चला जा रहा है। बिहार चुनाव इस बात का संकेत है कि इस देश की जनता का भरोसा अब मोदी और सिर्फ उनके इर्द.गिर्द सिमट चुकी भाजपा पर नहीं रहा। आने वाले दिनों में बंगाल और अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों से यह और भी साफ हो जाएगा।

बिहार में जीत के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने हर संभव तिकड़मबाजी की। उन्हें जब यह महसूस हुआ कि विकास का झूठा नारा कामयाब नहीं हो पाएगा तो उन्होंने साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के आजमाए हुए नुस्खे का इस्तेमाल किया। आरएसएस के इशारे पर गाय और बीफ के साथ जनता को यह डर भी दिखाया कि लालू.नीतीश पिछड़ों.दलितों को मिलने वाले आरक्षण का कुछ हिस्सा उनसे छीनकर अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने मर्यादा का पूरी तरह उल्लंघन किया और सड़कछाप भाषा और जुमलेबाजी पर उतर आए। लेकिन कहा गया है कि काठ की हांडी बार.बार नहीं चढ़ती। मोदी के सत्ता में आते ही आरएसएस और उससे जुड़े संगठन पूरी तरह बेकाबू हो गए और उन्होंने जमकर साम्प्रदायिकता का जहर फैलाना शुरू कर दिया। डेढ़ साल के दौरान महंगाई कई गुना

बढ़ गई और भगवा संगठनों ने ऐसा आतंक फैलाया कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। बीफ रखने की अफ़वाह फैला कर नोएडा के दादरी में एक शख्स की भाड़े की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर मुंह खोलना जरूरी नहीं समझा। वहीं, साक्षी महाराज, संगीत सोम और साध्वी प्राची ने ऐसे.ऐसे बयान दिए जो आग में घी झोंकने वाले थे। इधर, प्रधानमंत्री लगातार विदेशों का दौरा करते रहे और वहां प्रवासी भारतीयों के बीच तमाशों का आयोजन होता रहा, जिनमें भीड़ मोदी.मोदी का उन्मादी शोर मचाती रही। प्रधानमंत्री मोदी इस बात से खुश होते रहे कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। भाड़े के मीडिया ने भी उनकी ग़लतफ़हमी बढ़ाने में भूमिका निभाई और मोदी को पता नहीं चल सका कि दरअसल उनके पैरों तले ज़मीन खिसकती जा रही है। वे इस बात को भूल गए सिर्फ भाषणों और झूठे वायदों से जनता का पेट नहीं भरा जा सकता। साम्प्रदायिक आधार पर जनता को बांट कर हमेशा वोट नहीं लिए जा सकते। जनता एक बार धोखा खा सकती है, लेकिन बार.बार उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। बिहार के चुनाव ने यही साबित किया है। मोदी.अमित शाह की जोड़ी यह समझती रही है कि करोड़ों.अरबों रुपए झोंक कर और दुरभिसंधियां कर चुनाव जीते जा सकते हैं, पर बिहार ने उनके भ्रम को तोड़ दिया। लेकिन खास बात यह है कि मोदी.अमित शाह और इन्हें कठपुतले की तरह नचाने वाले आरएसएस को अभी भी यह इलहाम है कि वे अपनी तिकड़मबाजी से सब कुछ मैनेज करते रहेंगे। केंद्र की सत्ता हाथ में होने की वजह से उन्हें लगता है कि देश की जनता पर वे अपनी मन.मर्जी थोप सकते हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं है। मोदी को अब काफी विरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि राज्यसभा में उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं है और अध्यादेशों के माध्यम से वे लंबे समय तक राज नहीं कर सकते।

खास बात यह है कि मोदी के शासन में बेलगाम हो गए आरएसएस के उग्र तत्वों ने ऐसा कोहराम मचाना शुरू किया कि देश के लेखक, कलाकार और बुद्धिजीवी इनके खिलाफ़ हो गए हैं। लेखकों, कलाकारों ने अपने पुरस्कार लौटाए, वैज्ञानिकों ने विरोध किया। कहा जाने लगा कि मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटना चाहती है। देश के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकारों ने सरकार की भगवाकरण की नीतियों का खुल कर विरोध किया। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो. इरफान हबीब ने तो आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस तक से कर दी। प्रो. रोमिला थापर ने भी शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के भगवाकरण किए जाने का विरोध किया। इस सबसे माहौल भाजपा और मोदी के विरुद्ध बनता चला गया। लेकिन इससे कुछ सीख लेने की जगह मोदी ने इसे नज़रअंदाज़ किया, जिससे उनके समर्थकों का मनोबल बढ़ता गया और वे खुल कर आतंक फैलाने में लग गए। अभी भी वे आतंक फैलाने की नीति पर ही चल रहे हैं। लेकिन इससे उनका आधार और भी कमजोर होगा। आने वाले दिनों में मोदी के लिए जनसमर्थन कम होता चला जाएगा।

सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जिन मुद्दों के आधार पर केंद्र की सत्ता में आए थे, उन्हें पूरी तरह से भूल गए। उनके हर कदम ने यही दिखाया कि वे प्रचार के आधार पर सरकार चलाना चाहते हैं। झूठा प्रचार, जुमलेबाजी, इसके सिवा आम जनता को कुछ नहीं मिला। बिहार का चुनाव भी उन्होंने जुमलों के आधार पर जीतने की कोशिश की, पर वहां जातिवादी समीकरण साम्प्रदायिक समीकरण से मजबूत निकले। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए गए बयान ने लालू यादव और नीतीश कुमार को ऐसा मुद्दा दे दिया कि भाजपा बैकफुट पर आ गई। आखिरी दांव अमित शाह ने पाकिस्तान में दिवाली मनाए जाने वाला चला। उन्हें लगा कि पाकिस्तान के नाम पर कहीं वे बिहार चुनाव की वैतरणी पार न कर जाएं, पर मोदी.अमित शाह का साथ न तो गाय ने दिया और न पाकिस्तान ने। वहां नीतीश कुमार और लालू यादव के सामाजिक न्याय और मंडल पार्ट.2 का ही बोलबाला रहा। बिहार चुनाव ने कांग्रेस को भी जीवनदान दे दिया। उसे इतनी सीटें मिल गईं जिसके बारे में कांग्रेस नेतृत्व ने सोचा भी न होगा। सबसे बुरी हालत तो मुलायम सिंह की हुई, जिन्होंने ऐन वक्त पर मोदी के साथ आने का निर्णय लिया और अपने स्वाभाविक मित्रों का साथ छोड़ दिया। इसका खामियाजा उन्हें यूपी के चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। यह भी संभव है कि वे फिर से लालू.नीतीश के करीब आने की कोशिश करें।

बिहार चुनाव के पहले ममता बनर्जी ने महागठबंधन के पक्ष में बयान देकर दूरदर्शिता का परिचय दिया। अब बंगाल चुनाव में उनका मोर्चा जिसके साथ बने, पर इतना तय है कि भाजपा को वहां भी मात खानी पड़ेगी। कुल मिलाकर बिहार चुनाव परिणाम ने भाजपा विरोधियों में नया उत्साह पैदा कर दिया है। साथ ही, इससे भाजपा खेमे में निराशा और गुटबाजी बढ़ी है। भाजपा की सहयोगी शिवसेना भी अब मोदी से जमकर सौदेबाजी करेगी। बिहार चुनाव ने यह साबित कर दिया कि जनता ने कांग्रेस के बरसों के भ्रष्ट शासन से परेशान होकर और विकल्प के अभाव में भाजपा को विजयी बनाया था, पर मोदी ने विकास का एजेंडा छोड़ दिया, क्योंकि वह एजेंडा सिरे से था ही नहीं। उनका एजेंडा था हिंदुत्व का जो आरएसएस का एजेंडा है। बिहार की हार के बाद भी मोदी जी आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे और यही उनके पतन का कारण बनेगा। भाजपा से यह उम्मीद करना कि वह बिहार के चुनाव परिणाम से सबक लेकर कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी, पूरी तरह गलत होगा। मोदी की सरकार अब तक की सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार और जनविरोधी सरकार है। यह सिर्फ देशी.विदेशी पूंजीपतियों के हित में काम करने वाली है। फूट डालो और राज करो इसका मूल मंत्र है जो इसने अंग्रेजों की स्वामीभक्ति कर सीखा है।

अब सबसे बड़ा खतरा यह है कि हार की निराशा में आरएसएस कहीं देश में जहां.तहां दंगे फैलाने की साजिश न करे, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिससे इसे अब तक ताकत मिलती रही है। बहरहाल, देश में जो माहौल बनता जा रहा है, उसमें मोदी और उन्हें कठपुतले की तरह नचा रहे आरएसएस के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ेगा। बिहार ने साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफदेशव्यापी एक बड़े मोर्चे के निर्माण का संकेत दिया है। अगर ऐसा मोर्चा बनता है, तभी मोदी की सत्ता को चुनौती मिलेगी।

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा का 1-15 नवम्बर 2015 का अंक मिला, जिसमें राजनैतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक व धार्मिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख पढने को मिले। 'मोदी का गिरता भाव: नीतिश लालू की बढती नाव' तथा 'बिहार में नहीं गलेगी मोदी जी की दाल' लेखों में बिहार विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनैतिक दलों व गठबंधनों की स्थिति तथा जनतादल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस के महागठबंधन की विजय और भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए की पराजय का सही आंकलन किया गया है। इसके विपरीत कुछ मीडिया ने अपने एग्जिट पोल में दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर तथा कुछ ने एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की थी।

एक एजेंसी 'चाण्क्य' ने तो एनडीए को 150 सीट मिलने का दावा किया। सिर्फ़ एक ऐजेंसी 'ऐकेसिस एपीएम' के आंकलन का तीर सही निशाने पर लगा। उसने महागठबंधन को 169-183 तथा एनडीए को 58-70 सीट मिलने की भविष्यवाणी की। परंतु इस एजेंसी के आंकलन का किसी भी मीडिया ने हवाला नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बिहार में लगभग 30 चुनावी रैलियां करने और चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री की गरिमा को ही धूमिल करने के बावजूद मतदाता एनडीए की ओर आकर्षित नहीं हुए। चुनाव जीतने के लिये मोदी, अमितशाह व उनके सहयोगियों ने साम्प्रदायिकता का सहारा लिया तथा महागठबंधन के घटकों के बीच आपस में शक पैदा करने की कोशिश की और महागठबंधन की सरकार बनने की सूरत में वहां जंगलराज आने, भ्रष्टाचार व आतंकवाद के फ़ैलने और चिन तथा पाकिस्तान के सामने भारत के कमज़ोर पड़ने के बहाने मतदाताओं को भयभीत करने का भी प्रयत्न किया। परन्तु इन चालों का मतदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने महागठबंधन को भारी बहुमत से विजयी बनाया। बिहार पराजय ने मोदी और आरएसएस को मौका दिया है कि वे इस पराजय से सवक लें और साम्प्रदायिकता, अक्खड़पन, असहिष्णुता व झुठे वायदे करने की नीति को छोड़ें और देश के विकास के मुद्दे पर कार्य करें। जब से केन्द्र में मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी है तब से कट्टर हिन्दुत्ववादी शक्तियों द्वारा देश में असहिष्णुता की स्थिति उत्पन्न करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। जो भी तार्किक, विचारक, साहित्यकार, इतिहासकार, उदारवादी व समाज सुधारक समाज में व्याप्त अंधश्रद्धा, काला जादु, मूर्ति पूजा, कुरीतियों व गौ हत्या की अफ़वाहों तथा साम्प्रदायिकता की आलोचना करते हैं तो कट्टरवादी हिन्दू संगठन जैसे विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल, श्री राम सेना व सनातन संस्था के कार्यकर्ता उनका प्रतिरोध करने के साथ-साथ अब उनको धमकी देने व उनकी हत्या करने का प्रयास भी करने लगे हैं। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध तार्किक नरेन्द्र दाभोलकर, समाज सुधारक गोविन्द पंसारे तथा विचारक प्रोफ़ेसर एस.एस. कुलबर्गी की हत्या तथा अन्य लेखकों को दी गई धमकी तथा दादरी में गौ हत्या की अफ़वाह पर दो व्यक्तियों की हत्या पर जब मोदी सरकार ने कट्टर हिन्दुत्ववादी संस्थाओं पर कोई लगाम नहीं लगाई और साहित्य अकादमी ने साहित्यकारों की हत्या व उनको मिल रही धमकी की आलोचना तथा निंदा नहीं की तो साहित्यकारों, कलाकारों, वैज्ञानिकों आदि ने अपने पुरस्कारों को लौटाना शुरू कर दिये। इस पर सरकार की असहिष्णुता की नीति की देश तथा विदेश में आलोचना होने लगी। सरकार के हिन्दुत्ववादी संगठनों पर लगाम लगाने और उनके कारनामों की निंदा करने की बजाय लेखकों द्वारा किए जा रहे विरोध की आलोचना करना शुरू कर दी।

केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली सरकार के बचाव में उतरे और उन्होंने प्रधान मंत्री मोदी को असहिष्णुता का सबसे बड़ा शिकार बताते हुए लेखकों के विरोध को कारखाने में तैयार विद्रोह करार दिया। इस सम्बन्ध में लेख 'जेटली को गुहा का जवाब' के जरिए उचित व तार्किक उत्तर दिया गया है। 'लेखक संगठनों का साहित्य अकादमी की बेशर्म पैंतरेबाज़ी पर साझा प्रेस बयान-अकादमी अध्यक्ष तिवारी को चिंता सरकार की, लेखक जायें चूल्हे-भाड़ में' लेख में अकादमी अध्यक्ष की पैंतरेबाज़ी को उचित उज़ागर किया गया है। लेखकों के विरोध के प्रतिरोध में सरकार ने फ़िल्मी कलाकार अनुपम खेर के नेतृत्व में एक मार्च प्रोयोजित किया त्था अनुपम खेर के नेतृत्व में शिष्ट मंडल राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से भी मिला जो असहिष्णुता का एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आरएसएस से संबन्धि 'पांचजन्य' में वामपंथियों को टारगेट करते हुए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को आतंकवादियों तथा राष्ट्रद्रोहियों का गढ बताया गया है। इससे पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जेएनयू को वामपंथियों, आतंकवादियों व राष्ट्रविरोधी ताकतों का गढ बताते हुए उनको वहां से खदेड़ने के लिये अमेरिका की तरह वहां पर अर्द्धसैनिक बलों की टुकड़ी तैनात करने की वकालत की थी। कर्नाटक सरकार द्वारा टीपू सुल्तान की जयन्ती मनाने का संघ परिवार द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। कर्नाटक के जाने-माने एक्टर व लेखक गिरीश कर्नाड ने टीपू सुल्तान की प्रशंसा की तो ट्विटर में एक ट्वीट द्वारा कर्नाड को धमकी दी गई कि उनका भी प्रोफ़ेसर कुलबुर्गी जैसा हाल होगा। ऐसा प्रतित होता है कि मोदी एक तरफ़ तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ़ कट्टर हिन्दुत्ववादी संगठनों को देश में असहिष्णुता व साम्प्रदायिकता फ़ैलाने की मौन स्वीकृति दे रखी है।

स्तम्भ 'खबरदार-अबकि मुंह फ़टों की सरकार' में काल्पनिक साक्षात्कार के जरिए भाजपा सरकार के मन्त्रियों (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित) को बिना सोचे समझे बेलगाम बोलने की आदत का सही भंडा फ़ोड़ किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार है जबकि प्रधानमंत्री मोदी व उनकी सराकार के मंत्री कुछ का कुछ बोलकर प्रधानमंत्री व मंत्री पद की प्रतिष्ठा व गरिमा को गिरा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब विदेशी दौरे पर होते हैं तो वहां विदेशी धरती पर अपने भाषणों के दौरान भारतीय विपक्ष व अपने से पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करने से भी परहेज नहीं करते और भूल जाते हैं कि वे वहां विदेश में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं ना कि भाजपा का। लेख में मोदी सरकार को 'मुंह फ़टों की सरकार' उचित ही करार किया गया है। शेष सभी अन्य लेख भी उच्च स्तरीय तथा प्रशंसनीय है।

-प्रो. जुगल किशोर गुप्ता